

बिहार गजट असाधारण अंक

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ट 1945 (श0) (सं0 पटना 454) पटना, सोमवार, 5 जून 2023

विधि विभाग

अधिसूचना 5 जून, 2023

सं० एल०जी०-01-18/2022/4211 लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 12 मई, 2023 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द मालवीय, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 10, 2023] बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) का संशोधन करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावना। — चूँकि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 पर आधारित है एवं उक्त अधिनियम में भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.07.2018 को संशोधन किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 में संशोधन अपेक्षित है, जिससे कि उक्त अधिनियम को संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुकूल किया जा सके।

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम ''बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022'' कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तारण संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) इसे 26.07.2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- 2. बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) के धारा—2(ङ) का संशोधन :— बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा—2 की उपधारा (ङ) में शब्दों एवं अंकों ''धारा—13(1)(ङ)'' के स्थान पर ''धारा—13(1)(ख)'' शब्द एवं अंक रखे जायेंगे।
- 3. बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) में एक नई धारा का जोडा जाना :— बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) की धारा 26 के बाद एक नई धारा 27 निम्नवत् जोडी जायेगी:—
- 27. व्यावृत्ति । ऐसे संशोधन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

5 जून, 2023

सं० एल०जी०-01-18/2022/4212-लेज--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राष्ट्रपित द्वारा dated 12^{th} May, 2023 को अनुमत बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 10, 2023) का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रमेश चन्द मालवीय, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 10, 2023] The Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022 AN ACT

to amendment of The Bihar Special Courts Act 2009 (Bihar Act 5, 2010)

Preamble:- The Bihar Special Courts Act, 2009 (Bihar Act 5, 2010) is primarily based on the Prevention of Corruption Act, 1988 and the Act, was amended on 26.07.2018 by the Government of India. The Present amendment is proposed to ensure that the Bihar Special Courts Act, 2009 continues to remain in line with the Prevention of Corruption Act, 1988.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar seventy third year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement (1) This Act may be called "The Bihar Special Courts (amendment) Act, 2022."
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall be deemed to have come into force on the 26th day of July, 2018.
- 2. Amendment in Section-2(e) of Bihar Special Courts Act, 2009 (Bihar Act 5, 2010) In sub section (e) of Section 2 of the Bihar Special Courts Act, 2009 (Bihar Act 5, 2010), for the words and figures "section-13(1)(e)" the words and figures "Section-13(1)(b)" shall be substituted.
- 3. Insertion of new Section in Bihar Special Courts Act, 2009 (Bihar Act 5, 2010).- After section 26 of the Bihar Special Courts Act, 2009 (Bihar Act 5, 2010), the following new section 27 shall be inserted, namely:-
- "27 Savings.-Notwithstanding such amendments, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said act shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 454-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in